पिकिंग साइड्स इन वेस्ट एशिया

लेखक–हर्ष वी. पंत (प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किंग्स कॉलेज लंदन) , हसन अलहसन (किंग्स कॉलेज लंदन में पीएचडी छात्र)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

22 फरवरी, 2019

"भारत को विभिन्न पश्चिम एशियाई शक्तियों के बीच एक 'संतुलित दृष्टिकोण' बनाए रखने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।"

पिछले कुछ वर्षों में, इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ भारत के संबंधों के पाठ्यक्रम से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान, भारत आखिरकार पश्चिम एशिया के संदर्भ में अपने पारंपरिक 'संतुलन' दृष्टिकोण से दूर जा रहा है। मोदी सरकार ने ईरान के बजाय तीन क्षेत्रीय शक्तियों के साथ काम करने के मुद्दे को प्राथमिकता दी है, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) की यात्रा और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रस्तावित नई दिल्ली की यात्रा के बाद अधिक प्रबल होते दिख रहा है।

क्षेत्रीय यथार्थ

1990-91 के खाड़ी युद्ध के बाद से, भारत ने आधिकारिक तौर पर पश्चिम एशिया के संदर्भ में एक "संतुलित दृष्टिकोण" को अपनाया है, जो गुटनिरपेक्षता की विरासत के रूप में है। यद्यपि इस दृष्टिकोण ने भारत को क्षेत्रीय विवादों में शामिल नहीं होने और

ईरान, इजरायल और सऊदी अरब सहित क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ संबंधों को सफल बनाने की अनुमति दी है, लेकिन इस नीति ने क्षेत्र में अपने भू-राजनीतिक हितों को दबाने की भारत की क्षमता को भी बाधित किया है।

देखा जाये, तो भू-राजनीतिक रूप से, एमबीएस और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद (MBZ) ने पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम ब्रदरहुड सहित राजनीतिक इस्लामवादी समूहों के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया है। सबसे विशेष रूप से, इन्होंनें 2013 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसी का समर्थन मुस्लिम ब्रदरहुड से सत्ता के अधिग्रहण में किया। स्वाभाविक रूप से, यह उन्हें इजराइल के करीब लाता है जो सीरिया में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित बलों सहित इस्लामी आतंकवादी समूहों के बढ़ते खतरे का सामना कर रहा है।

सऊदी अरब और यूएई द्वारा राजनीतिक इस्लामी समूहों के प्रभाव को कम करने के लिए अभियान भी उन्हें भारत के करीब लाता है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान, 'खुफिया जानकारी साझा करने सहित हर तरह से सहयोग करने' का संकेत दिया है। हाल के महीनों में, यूएई ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के संबंध में कम से कम तीन वांछित संदिग्धों के प्रत्यर्पण के साथ, भारत के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया है।

रक्षा और ऊर्जा की जरूरत

इस बीच, इजरायल के साथ भारत की रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पहले से ही अपनी सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण अभियान के लिए उपयोगी साबित हुई है। 1998 में, इजरायल ने भारत को कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी स्थिति की बहुमूल्य खुफिया जानकारी प्रदान की थी। हाल ही में, भारत और इजराइल ने 777 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर सहमति जताई है, जो बराक-8 (सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल) का समुद्री संस्करण विकसित करने से संबंधित है, जिसका भारत ने जनवरी में एक सफल परीक्षण भी किया था।

भारत ने कथित तौर पर भारतीय वायु सेना के लिए 54 हार्प हमले के ड्रोन और दो एयरबोर्न चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (AWACS) खरीदने के लिए इजरायल से 800 मिलियन डॉलर से अधिक की कीमत पर सहमति व्यक्त की है। अपने तकनीकि परिष्कार और बेहतर संबंधों के कारण, इजराइल सैन्य प्रौद्योगिकी के लिए भारत के शीर्ष आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक बन गया है।

आर्थिक रूप से, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की कम तेल की कीमतों के बावजूद निवेश जुटाने की क्षमता भारत के साथ उनके संबंधों में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। निवेश में सऊदी अरामको और भारत में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द्वारा भारतीय कंसोर्टियम के साथ 44 बिलियन डॉलर की तेल रिफाइनरी शामिल है। नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान, एमबीएस ने कहा कि वह अगले कुछ वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर के सऊदी निवेश को देख रहे हैं, जिसमें सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा दो एलएनजी प्लांट स्थापित करने की योजना भी शामिल है।

ईरान की हिस्सेदारी

इसके विपरीत, इस्लामिक उग्रवाद को ईरान का समर्थन, जहाँ इसने लेबनान और सीरिया में इस्लामिक समूहों और सहयोगी सेनाओं को उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी की मदद की है, इजरायल के साथ तनाव में वृद्धि का कारण बना है,जो जनवरी में सीरियाई धरती पर ईरानी ठिकानों के खिलाफ हवाई हमले का कारण बना। हालांकि, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 27 सदस्यों और भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 40 सदस्यों पर जानलेवा हमले भारत और ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ एक मंच पर लाने की संभावना को बढ़ा देते हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण से, अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान को एक अविश्वसनीय आर्थिक भागीदार के रूप में बदल दिया है। नवंबर में अमेरिका से ईरान से ऊर्जा आयात पर छह महीने की छूट प्राप्त करने के बावजूद, भारत वैकल्पिक स्रोतों को खोजने की योजना बना रहा है। इस बीच, ईरान में भारतीय निवेश, जिसमें चाबहार और फरजाद बी गैस क्षेत्र में शाहीद बेहेश्टी कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, ईरान के साथ व्यापार करने पर गंभीर बाधाओं को दर्शाता है।

हालांकि, भारत का इजराइल, सऊदी अरब और यूएई के प्रति झुकाव एक जोखिम-मुक्त कदम नहीं है। ईरान पश्चिम एशिया में बहुत अधिक प्रभाव बनाने में सक्षम है और अमेरिका के खिलाफ तालिबान को किनारे करके अफगानिस्तान में घटनाओं को आकार देने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक रणनीतिक निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, जो मध्य-एशिया तक फैले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारे (INSTC) और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते को बायपास करने के लिए सुविधा का उपयोग करने की उम्मीद को बढ़ाता है।

फिर भी, जैसा कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है, इजरायल, सऊदी अरब और यूएई ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित मध्य पूर्व सुरक्षा गठबंधन (एमईएसए) के तहत ईरान के खिलाफ अधिक निकटता से समन्वय किया है। सीरिया के मोर्चे पर ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में वृद्धि से पता चलता है कि तनाव जल्द ही कम होगा, इसकी संभावना नहीं है।

वर्तमान में, मोदी सरकार ने इसका लुफ्त उठाया है। व्यावहारिक रूप से एक 'संतुलित' दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए, तो मोदी सरकार ने इजराइल और खाड़ी राजतंत्रों पर अपना दांव लगाते हुए ईरान के साथ संबंधों को किनारे कर दिया है।

GS World टीम...

लुक वेस्ट पॉलिसी

क्या है?

- हाल के समय में भारत ने यूरोप एवं अमेरिका के साथ-साथ पश्चिम एशिया के साथ भी संबंधों को मजबूती देने का प्रयास किया है।
- ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजरायल, फिलिस्तीन जैसे देशों के साथ भारत ने घनिष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया है। भारत की इस नीति को 'लुक वेस्ट पॉलिसी' का नाम दिया जा रहा है।

भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी के सकारात्मक पक्ष

- भारत ने इजरायल के साथ संबंधों को मजबूत बनाया है, किंतु फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को बिगड़ने नहीं दिया है।
- इसी प्रकार भारत ने ईरान के साथ-साथ सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात से भी संबंधों को सशक्त स्थिति में रखा है।
- आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा एवं वैश्विक ध्रुवीकरण के संबंध में भारत एवं पश्चिमी एशियाई देशों की चिंतायें एक जैसी हैं।
- भारत एवं पश्चिम एशियाई देशों के बीच पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट बढ़ता जा रहा है। भारतीय व्यंजन एवं फिल्में पश्चिम एशियाई देशों में पसंद की जा रही हैं।
- बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा पश्चिम एशियाई देशों में निवास कर रहे हैं। ये न सिर्फ भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते हैं, बल्कि भारी मात्रा में रेमिटांस भी भारत में भेजते हैं।

भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी के नकारात्मक पक्ष

- पश्चिम एशियाई देशों के बीच आपसी संघर्ष लगातार जारी है, जो भारत की नीति को अधिक कारगर नहीं होने दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, यमन, सीरिया में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। इसी प्रकार ईरान एवं सऊदी अरब के बीच मतभेद हैं।
- अरब लीग एवं जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद्) जैसे संगठन निष्क्रिय बने हुए हैं।
- भारत की 'लुक ईस्ट नीति' सफल रही है क्योंकि पूर्व में आसियान जैसा मजबूत संगठन है। जबकि पश्चिम एशिया में आसियान जैसा कोई मजबूत संगठन नहीं है। अत: भारत की 'लुक वेस्ट नीति' की सफलता संदेहास्पद है।

भारत के द्वारा उठाये जाने वाले कदम

- भारत को पश्चिम एशियाई देशों के आपसी विवादों में नहीं उलझना चाहिए तथा प्रत्येक देश से द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
- पश्चिम एशियाई देशों के साथ आर्थिक मुद्दों, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट तथा सूचना-प्रौद्योगिकी के मामले में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. ब्राक-8 मिसाइल के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
2. इसे संयुक्त रूप से इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements-

1. It is a surface to air missile.
2. It was jointly developed by the Israel Aerospace Induistries and DRDO.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारत को विभिन्न पश्चिमी एशियाई शक्तियों के बीच एक 'संतुलित दृष्टिकोण' बनाये रखने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए? चर्चा कीजिए।

Q. Which type of challenges India has been facing in maintainig 'Balanced viewpoint' among the various West-Asian powers? What type of strategy India should adopt for dealing with these challenges? Discuss.

(250 Words)

नोट : 21 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।